

[श्री बीबा भाई]

को मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। मजदूरों को भुगतान करने के क्रम में अभी तक अपर्याप्त प्रयत्न किए गए हैं। मजदूर पेमेंट नहीं मिलने से परेशान हो गए हैं। इससे हमारे प्रधान मंत्री जी के बारह सूची प्रकाल कार्यक्रम को प्रवर्धन हो रही है। अतः राज्य सरकार को निदेश दिया जाए कि वह बड़ा हुआ मजदूरों का भुगतान अधिकतम कराए।

(iii) STEPS TO MEET THE LEGITIMATE DEMANDS OF HANDLOOM INDUSTRY.

SHRI K. KUNHAMBU (Cannanore): Sir, the handloom weavers of Kerala have gone on a strike demanding protection to the handloom industry and higher wages and other benefits for the workers.

Many organisations connected with the handloom industry have made repeated representations to the Central Government demanding a reduction in the price of yarn. The Kerala Government itself has requested the Centre to do something about it. But, strangely enough, the Central Government went on increasing the price of yarn. In March last, the Prime Minister had given an assurance that the matter would be given sympathetic consideration. But the Government has not cared to implement that assurance. The price of yarn has gone upto between 45 and 47 per cent. In this situation, it is essential that the price be brought down to 1973 level, and it has to be maintained at this level for some more time so that the handloom industry is not ruined.

The handloom industry is a decentralised one in many areas. As a result of that, the workers are deprived of minimum wages and other benefits. The Central Government should take initiatives to re-organize this industry on factory lines and on force national minimum wages.

I, therefore, request the Government to take immediate steps so that the legitimate demands of the workers in the handloom industry are met.

(iv) REPORTED NON-AVAILABILITY OF SUGAR AND OTHER RATIONED ITEMS AT FAIR PRICE SHOPS IN NORTH AVENUE AND OTHER PARTS OF DELHI.

श्री रामानंदर शास्त्री (पटना) : उपरोक्त मस्युदा, राशन की दुकानों में चीनी नहीं मिलती है दिल्ली के प्रेसिडेंट एस्टेट स्थित मार्केट में राशन की दो दूकानें हैं। उनके प्रमुख नागरिकों के अतिरिक्त मार्ब एवेन्यू में रहने वाले संसद-सदस्यों को भी राशन, चीनी आदि वस्तुएं मिलती हैं। परन्तु वास्तविक है कि जून माह में उक्त दुकानों के काउंटरकारी उपभोक्ताओं को एक दाना भी चीनी नहीं मिली है। अधिकारिता उपभोक्ताओं को जूले काजर से सात रुपये किलो के भाव से चीनी खरीद कर काम चलाना पड़ रहा है। अतः उनकी कठिनाइयों का अनुमान प्रासानी के साथ लगाया जा सकता है।

उपभोक्ताओं को माह में दो बार चीनी मिलती है, पर जून माह में एक बार भी नहीं मिली। दुकानदार बराबर यही जवाब देते हैं कि स्टॉकिस्ट ने उन्हें चीनी की सप्लाई नहीं की है, पाहुक चाहे तो अन्यत्र जा सकते हैं। ग्राहकों को इस माह में यानी जुलाई में भी अब तक चीनी का दर्शन नहीं हुआ है। राशन की भी यही स्थिति है, कभी चावल मिलता है तो गहू नहीं और गेहू मिलता है तो चावल नहीं।

चीनी नहीं मिलने की शिकायत एक सांसद ने लोक-सभा के अध्यक्ष से चार बार की, सांसद ने आपूर्ति मंत्री से भी कहा। लोक सभा अध्यक्ष ने आपूर्ति मंत्री को इस बारे में पत्र भी लिखा, पर जवाब नदारद। 27 जून को कुछ सांसदों ने दिल्ली में चीनी के अभाव तथा मूल्य वृद्धि का महत्वपूर्ण सवाल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया, उक्त दुकानों की भी चर्चा की गई, जवाब में कृषि मंत्री ने चीनी की कठिनाई दूर करने का आश्वासन भी दिया, परन्तु दुःख है कि उनका आश्वासन कोरा आश्वासन बन कर रह गया।

दिल्ली प्रशासन के लिये यह विचार करने योग्य बात है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी संसद-सदस्यों समेत आम उपभोक्ताओं को राशन की दुकानों से चीनी नहीं मिल रही है। दुकानदार भागा फिर रहा है। इस सम्बन्ध में आपूर्ति मंत्री को मदन में बहुरव्य देकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिये।

(v) STEPS TO CLEAR THE PENDING CASES IN CALCUTTA INDUSTRIAL TRIBUNAL

SHRI SUSHIL BHATTACHARYYA (Burdwan): A good number of cases are pending at Calcutta Industrial